

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास।
- केन्द्र सरकार ने चैलचौक-पंडोह और मण्डी-बजौरा मार्ग के सुदृढीकरण के लिए 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृत।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा— स्वस्थ रहने के लिए मिलेट्स का उपयोग जरूरी।
- प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोविन्द ठाकुर ने राज्य सरकार पर उत्प्रावास अधिनियम 1983 के उल्लंघन का लगाया आरोप।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने आज मण्डी ज़िले के जोगिन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 76 करोड़ 31 लाख रुपए की 8 परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर जोगिन्द्रनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार कई कड़े फैसले ले रही है जिससे प्रदेशवासियों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के दौरान जोगिन्द्रनगर क्षेत्र के लिए 2 करोड़ 26 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 32 सड़कों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार पूरी धनराशि प्रदान करेगी और जोगिन्द्रनगर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ करने के लिए चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल ईजन की सरकार ने हिमाचल की संपदा को लुटाया जबकि वर्तमान सरकार ने चोर दरवाज़ों को बंद किया है। उन्होंने कहा कि भूभू जोत टनल का मामला प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया गया है और जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 20 महीने में सरकार ने भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगाई है और 2 हजार 2 सौ करोड़ रुपए का राजस्व कमाया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मण्डी ज़िला की बेटियों के सशक्तिकरण के लिए देई कार्यक्रम का शुभारम्भ भी किया और 7 बच्चियों को सम्मानित किया।

विक्रमादित्य

केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने चैलचौक-गोहर-पंडोह और मण्डी-कमांद-कटौला-बजौरा मार्ग के सुदृढीकरण व रखरखाव के लिए 21 करोड़ 5 लाख की राशि स्वीकृत की है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि चैलचौक-पंडोह के लिए 9 करोड़ 16 लाख जबकि मण्डी-बजौरा मार्ग के लिए 11 करोड़ 89 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाल ही के दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उनसे इन सड़क मार्गों के सुदृढीकरण व रखरखाव के लिए पर्याप्त धनराशि का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि मण्डी-बजौरा सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत होने से स्थानीय लोगों और कुल्लू की ओर जाने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी। विक्रमादित्य सिंह ने ये धनराशि स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।

इस बीच, शिमला में आज एक कार्यक्रम में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करना उनकी प्राथमिकता है जिसके लिए वह लगातार केंद्र से भी सहयोग लाने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी भरपूर मदद कर रही है।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केन्द्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। अनुराग ठाकुर इन दिनों इंटर पार्लियामेंट्रीय यूनियन की विभिन्न बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वीट्ज़रलैंड के जेनेवा की यात्रा पर हैं। उन्होंने आज जेनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्ज ब्रेंडे से मुलाकात की और भारत की आर्थिक वृद्धि पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी संस्थाओं और रेटिंग एजेंसियों ने भी दावा किया है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज़ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान अगले 5 वर्ष में 16 प्रतिशत से बढ़ कर 18 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जाइका वानिकी परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के प्राकृतिक उत्पादों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मिलिट्स का उपयोग स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, ऐसे में प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कल शिमला के समीप जुन्गा में आयोजित चार दिवसीय प्लाइंग फ़ैस्टिवल व हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 के शुभारम्भ अवसर पर वानिकी परियोजना के स्टॉल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक उत्पादों से किसानों की आजीविका में सुधार होगा और उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। इस दौरान मुख्य परियोजना निदेशक समीर रस्तोगी ने राज्यपाल को परियोजना की गतिविधियों व स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के बारे में अवगत करवाया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मण्डी ज़िले में कोटली उपमण्डल के समराहन में बागवानी विभाग के फल संतति व प्रदर्शन उद्यान केन्द्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 1970 के दशक में बने इस उद्यान को विकसित किया जाएगा ताकि लोगों को बागवानी के प्रति आकर्षित किया जा सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एच.पी. शिवा परियोजना के तहत समराहन में 2 सौ बीघा भूमि में कलस्टर विकसित किया जाएगा और इस क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल फल लगाए जाएंगे।

वाल्मीकि जयंती

आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। चम्बा के बकलोह कैंट में महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के महान कवि और रामायण के रचयिता थे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के जीवन की अनेक प्रेरणात्मक विशेषताएं हैं जिनका अनुसरण कर हम आज भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उनके कार्यों से हमें सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है। सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सभी को समरसता व एकता का संदेश दिया था। उन्होंने सभी से महर्षि वाल्मीकि के दिखाए मार्ग पर चलने का आग्रह किया।

गोविन्द ठाकुर

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर 5 युवाओं को रोज़गार के लिए सऊदी अरब भेजने के मामले में उत्प्रवास अधिनियम 1983 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। मनाली में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना आवश्यक कानूनी अनुमति के इन युवाओं को विदेश में रोज़गार दिलाने की प्रक्रिया को पूरा किया है जो न केवल कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है बल्कि इन युवाओं की सुरक्षा व अधिकारों पर भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि उत्प्रवास अधिनियम 1983 के प्रावधानों के तहत किसी भी भारतीय नागरिक को विदेश में रोज़गार के लिए भेजने से पहले उत्प्रवास के महासंरक्षक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। गोविन्द ठाकुर ने कहा कि इस तरह की लापरवाही विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से उत्प्रवास अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है ताकि विदेश जाने वाले श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। गोविन्द ठाकुर ने कहा कि उन्होंने इस मामले को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के समक्ष भी उठाया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

टीबी उन्मूलन

राज्य सरकार प्रदेश में टीबी उन्मूलन की दिशा में कई कदम उठा रही है। इसके तहत रविवार सक्रिय केस फाईंडिंग अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस दौरान आशा कार्यकर्ता साप्ताहिक रूप से अति संवेदनशील आबादी की स्क्रीनिंग करती हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष 23 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और 2 सौ 19 टी.बी. रोगियों का ईलाज किया गया। इसके अलावा लोगों को टी.बी. रोग के बारे में जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में 19 अक्टूबर को एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा जिसमें टीबी को खत्म करने के रोड मैप पर चर्चा की जाएगी।

अनुबंध कर्मचारी

सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार से सितम्बर तक 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अपनी मांगों को लेकर महासंघ ने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है लेकिन अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को पहले साल में दो बार नियमित किया जाता था, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार मार्च में एक बार ही नियमित किया जा रहा है। कामेश्वर शर्मा ने कहा कि ये नियम पहले भर्ती हो चुके कर्मचारियों पर लागू नहीं होना चाहिए।